DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, सोमवार, 29 मई 2023 DATED

अवैध रंगाई फैक्टरियों की जांच होगी

निर्देश

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में अवैध रंगाई फैक्टरियों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने फिर सख्ती शुरू कर दी है। एनजीटी ने उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त निगरानी समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) फैक्टरियों की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अनुपालन स्थिति पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बिंदापुर, मटियाला, रणहौला, ख्याला, मीठापुर, बदरपुर, मुकुंदपुर और किराड़ी इलाकों में बिना अनुमति के रंगाई कारखाने चलने का दावा किया गया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने कहा कि सीपीसीबी और डीपीसीसी सहित अन्य संबंधित प्राधिकरणों के समन्वय से मामले को देखना है। निगरानी समिति समेत अन्य विभागों को कहा है कि वह इस पर जांच कर तीन महीने के भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई करें। एनजीटी ने इस मामले में अगली सुनवाई चार अक्तूबर तय की है।

21 अवैध इकाइयों की सूची एनजीटी के सामने पेश की गई

04 अक्तूबर को एनजीटी इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा

याचिकाकर्ता की ओर से ये आरोप लगाए गए

500 से फैक्टरियां खुले इलाकों, नजफगढ़ और स्वरूप नगर नाले में गंदा पानी छोड़ रही हैं, भूजल निकाल रही हैं। कोई अपशिष्ट उपचार संयंत्र भी नहीं लगे हैं। क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण उच्च पीएच, मैलापन, खराब गंध, कुल घुलित ठोस, कुल निलंबित ठोस, जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड, भारी धातुओं और कम घुलित ऑक्सीजन को दर्शाता है। याचिका में 21 अवैध इकाइयों का नाम भी दिया गया है।

पहले भी दिया जा चुका है आदेश

वर्ष 2004 में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर चल रही औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने या बंद करने का निर्देश दिया था। इसे रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की एक निगरानी समिति का गठन किया गया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI ---DATED--- MAY 28, 2023

187-year-old church to get its glory back

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The restoration work of the 187-year-old St James' Church, which was started by Delhi Development Authority (DDA) six months ago, is likely to be completed by June 30. This was disclosed by lieutenant governor VK Saxena's office after he inspected the church at Kashmere Gate on Saturday.

Officials said that being built in the year 1836 AD, the structure needed urgent repairs, as plaster from the walls had either come off or deteriorated and the masonry was missing in several sections. During his visit, the LG also stressed that the church building and its vicinity should be developed in such a way that it becomes a prominent landmark in the city as it once used to be. Saxena instructed the officials to strictly ensure the originality of the heritage building.

Officials said the preservation of the heritage has been a focus area of the LG ever since he assumed office in May last year and he had personally initiated and monitored the restoration of heritage structures such as Gole Market, Anang Tal Baoli, Nizamuddin Basti and Mehrauli Archaeological Park among others.

The LG has instructed the officials to strictly ensure the originality of the heritage building

St James' Church is one of the oldest churches in the city and is part of the churches of North India Diocese of Delhi. Restoration of the church assumes great significance as this area has close proximity with several historical monuments in Old Delhi and are frequently visited by thousands of visitors every day.

According to officials, the conservation work at the interior and exterior of the main building and on the parapet at the terrace level is in progress with the permission of the Archaeological Survey of India.

The church and its complex cover a total of 10 acres. The present compound of the church has a rectilinear form and the building is situated in the centre. The cemetery lies in the northern part and contains graves of the members of Skinner's family and many important personalities of Delhi. With the widening of Lothian Road in 1914, the church compound lost 3,500 square ft area.

The church is based on a Greek cross plan with a fine colonial classical architecture and a Florentine dome. The compound walls have four gateways which lead up to the church through driveways.

Earlier used as servant's quarters, those rooms are being used as storage space at present. The toilet block also lies in this row of rooms. The old people's home and the Parish Hall were added within the complex during the time of Reverend Robinson in 1940. These two structures were designed by architect Walter George who's been instrumental in helping Edwin Lutyens and Herbert Baker in designing the capital city. The southern side of the complex was built upon with a two-storey building having four different units in 1957.

This continues to be used as the priest's residence along with offices of Indian Society for Promoting Christian Knowledge. The boundary wall of the church complex is made in brick masonry and has been drastically changed with time. Considering the attempts of theft and other security reasons, the height of the new boundary wall has also been increased.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times APERS

LG TAKES STOCK OF ST. JAMES' CHURCH REPAIR WORK

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Saturday visited the 187-year-old St James' Church at Kashmere Gate and took stock of the restoration and renovation work being undertaken by the Delhi Development Authority (DDA) there. The restoration of the heritage church started nearly six months ago and is scheduled to be completed by June 30 this year, officials said.

The LG instructed officials to strictly ensure that the originality of the heritage structure is retained. "The church building and its vicinity should be developed in such a way that it becomes a prominent landmark in the city," LG Saxena said. He also visited the Election Museum, located inside the old St Stephen's College building at Kashmere Gate. HTC

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 28 मई, 2023

एलजी ने लिया सेंट जेम्स चर्च के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को कश्मीरी गेट स्थित 187 वर्ष पुराने हेरिटेज सेंट जेम्स चर्च का दौरा किया और डीडीए द्वारा यहां किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। चर्च के जीर्णोद्धार का काम लगभग छह माह पहले शुरू हुआ था। इस कार्य को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। डीडीए के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एलजी ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में चुनाव संग्रहालय का भी दौरा किया।

एलजी ने चर्च के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को हिदायत दी कि इतिहास को संजोती इस धरोहर की मौलिकता को बरकरार रखना सुनिश्चित किया जाए। सेंट जेम्स चर्च (स्किनर्स चर्च के रूप में भी जाना जाता है) और इसे दिल्ली में भारत के ब्रिटिश वायसराय के आधिकारिक चर्च के रूप में जाना जाता है। एलजी ने जोर देकर कहा कि चर्च की इमारत और उसके आसपास के क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि यह शहर में आकर्षण का खास केंद्र बन जाए। डीडीए के अधिकारियों ने एलजी को बताया कि नवीनीकरण का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इमारत को चर्च प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा, जो इस चर्च को फिर से जनता को समर्पित करेगा। सेंट जेम्स चर्च शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और दिल्ली के उत्तर भारत प्रांत के चर्च का हिस्सा है। यह क्षेत्र पुरानी दिल्ली की कई ऐतिहासिक स्मारकों के काफी करीब है।

दिल्ली के सबसे पुराने सेंट जेम्स चर्च का निरीक्षण करते एलजी • सौ. राजनिवास

- छह माह पहले शुरू किया गया था चर्च का जीर्णोद्धार कार्य
- मुख्य निर्वाचन कार्यालय में चुनाव संग्रहालय का भी किया निरीक्षण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS दैनिक भास्कर NEW DELHI SUNDAY MAY 28, 2023 -----DATED----------

एलजी ने 187 साल पुराने चर्च का निरीक्षण किया

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित 187 साल पुराने सेंट जेम्स चर्च के रेनोवेशन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को चर्च के मौलिक स्वरूप को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एलजी कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सेंट जेम्स चर्च के रेनोवेशन का काम लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। उन्होंने उम्मीद जताई कि चर्च के रेनोवेशन का काम आगामी 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सेंट जेम्स चर्च को भारत की आजादी से पहले दिल्ली में देश के वायसराय का आधिकारिक चर्च माना जाता था।

एलजी वीके सक्सेना ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सेंट जेम्स चर्च की इमारत और उसके आसपास के क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि यह शहर की खूबसूरती में प्रमुख नगीना बन जाए, जैसा कि यह पहले कभी हुआ करता था।

वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेंट जेम्स चर्च दिल्ली के लोगों को फिर से समर्पित करने के लिए प्रबंधन निकाय को सौंप दिया जाएगा। एलजी सक्सेना ने पिछले एक साल में गोल मार्केट, अनंग ताल बावली, निजामुद्दीन बस्ती और महरौली पुरातत्व पार्क जैसी विरासतों के जीर्णोद्धार कार्य की निगरानी की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer. NEW DELHI I MONDAY I MAY 29, 2023

NGT orders SC panel, CPCB, DPCC to probe illegal dyeing units

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The National Green Tribunal has directed the Supreme Court-appointed monitoring committee, the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) to look into illegal dyeing units in the national capital and to jointly file an action taken report on the compliance status in respect of the units named in the application.

The Tribunal was hearing a petition claiming that dyeing factories were operating without consent or permission in the Bindapur, Matiala, Ranhola, Khyala, Meethapur, Badarpur, Mukundpur and Kirar areas of the national capital.

A bench of Chairperson Justice AK Goel said the monitoring committee appointed by the Supreme Court has to look into the matter in coordination with other authorities concerned, including the CPCB and the DPCC.

In 2004, the Supreme Court directed the shifting or closure of industrial activities operating in violation of the master plan of Delhi and also laid down the monitoring mechanism.

For stopping illegal industrial activities, the apex court formed a monitoring committee comprising Delhi's chief secretary, police commissioner, municipal commissioner and the Delhi Development Authority vice-chairman.

"The report may mention consent status and compliance status with reference to disposal of effluents into the drain... location of these units in the non-conforming areas and proposed remedial actions within three months...," the bench, also comprising Judicial Member Justice Sudhir Agarwal and Expert Member A Senthil Vel, said. The matter has been posted for further proceedings on October 4.

The petition alleged that there are over 500 such factories discharging effluents in open areas, the Najafgarh drain or the Swaroop Nagar drain, besides illegally extracting groundwater. It also alleged that there are no common effluent treatment plants for treating the effluents.

"Testing of water quality in the area shows high pH, turbidity, bad odour, total dissolved solids, total suspended solids, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, chloride, nitrate, sulphuric acid, heavy metals and low dissolved oxygen. Effluents are highly toxic, carcinogenic and hazardous to the health of the people residing nearby," the petition had said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

sunday pioneer
NEW DELHI | SUNDAY | MAY 28, 2023 PAPERS DATED

LG visits St James' Church to review restoration

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena on Saturday visited the 187-year-old heritage St James' Church at Kashmere Gate and took stock of the restoration and renovation work being undertaken by the Delhi Development Authority (DDA). The restoration of the Church began nearly six months ago and the same is scheduled for completion by June 30. He was accompanied by Vice Chairman, DDA, Experts and other senior officials. He also visited the Election Museum at Chief Electoral Office, Delhi.

Saxena, while inspecting the renovation work of the Church, instructed the officials to strictly ensure that the originality of the heritage structure is retained, while curation and restoration took place. St. James' Church (also known as Skinner's Church), is known to be the official church of the British Viceroy of India in Delhi.

The Lt Governor stressed that the Church building and its vicinity should be developed in such a way that it becomes a prominent landmark in the city, as it once used to be. DDA officials informed Saxena that the renovation work would be completed by June 30 and the building would be handed over to the Church management for further rededication to the people of Delhi.

St James' Church is one of the oldest churches in the city and is part of the Church of North India Diocese of Delhi. Restoration of the Church assumes great significance as this area has close proximity with several historical monuments in Old Delhi-Walled City and are frequented by thousands of visitors every day.

millenniumpost
SUNDAY, 28 MAY, 2023 | NEW DELHI

LG inspects restoration work of St James' Church

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Friday inspected the ongoing restoration of the 187-year-old St James' Church at Kashmere Gate undertaken by the Delhi Development Authority (DDA) and asked for ensuring the originality of the heritage building.

Restoration of the church, also known as Skinner's Church, began nearly six months ago and it is scheduled to complete by June 30, a statement from the LG office said.

Taking stock of the renovation work, Saxena instructed the officials to strictly ensure that the originality of the heritage structure is retained during curation and restoration.

The church was considered to be the "official" church of the viceroy of India in Delhi before Independence, the statement said.

The LG stressed that the church building and its vicinity should be developed in such a way that it becomes a prominent landmark in the city, as it once used to be.

"DDA officials informed the LG that renovation work would be completed by June 30 and the church building will be handed over to the management body for further rededication to the people of Delhi," it said.

MPOST

पंजाब केसरी
DELHI
28 मई, 2023 ▶ रविवार

जीर्णोद्धार कार्य का लिया जायजा, 30 जून तक काम पूरा करने का दिया आश्वासन

एलजी ने दिल्ली के सबसे पुराने सेंट जेम्स चर्च का किया दौरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शनिवार को कश्मीरी गेट स्थित 187 साल पुराने हेरिटेज सेंट जेम्स चर्च का दौरा किया और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यहां किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। चर्च के जीर्णोद्धार का काम लगभग 6 माह पहले शुरू हुआ था।

इस कार्य को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीडीए के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एलजी ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय में चुनाव संग्रहालय का भी दौरा किया। सक्सेना ने चर्च के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को हिदायत दी कि इतिहास को संजोती इस धरोहर की मौलिकता को बरकरार रखना सुनिश्चित किया जाए। सेंट जेम्स चर्च (स्किनर्स चर्च के रूप में भी जाना जाता है) और इसको दिल्ली में भारत के ब्रिटिश वायसराय के आधिकारिक चर्च के रूप में जाना जाता है। एलजी

ने जोर देकर कहा कि चर्च की इमारत और उसके आसपास के क्षेत्र को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि यह शहर में एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। डीडीए के अधिकारियों ने सक्सेना को बताया कि नवीनीकरण का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इमारत को चर्च प्रबंधन को सौंप दिया जाएगा जो इस चर्च को फिर से जनता को समर्पित करेगा। सेंट जेम्स चर्च शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है और दिल्ली के उत्तर भारत प्रांत के चर्च का हिस्सा है। यह क्षेत्र पुरानी दिल्ली की कई ऐतिहासिक स्मारकों के काफी करीब है इसलिए भी इस चर्च का जीर्णोद्धार काफी मायने रखता है। सक्सेना ने चुनाव संग्रहालय का भी दौरा किया जो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में स्थित है। उन्होंने संग्रहालय की स्थापना के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय चुनावों की उल्लेखनीय यात्रा को दर्शाता है, जिसने दुनिया भर के देशों को चुनावी प्रबंधन के मूल्यों को संरक्षित करने और संजोने के लिए प्रभावित किया है। एलजी ने अधिकारियों से स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को संग्रहालय देखने के लिए प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास करने की भी अपील की। एलजी कहना था कि उनके लिए सीखने का यह एक अच्छा अनुभव हो सकता है। यहां बता दें कि एलजी का एक फोकस विरासतों के संरक्षण का रहा है। उन्होंने पिछले साल मई में कार्यभार संभालने के बाद से व्यक्तिगत रूप से गोल मार्केट, अनंग ताल बावली, निजामुद्दीन, बस्ती और महरौली पुरातत्व पार्क समेत कई अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के जीर्णोद्धार की पहल और निगरानी की है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- millenniumpost
NEW DELHI | MONDAY, 29 MAY, 2023

NGT directs monitoring committee, CPCB and DPCC to look into city's 'illegal' dyeing factories

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The National Green Tribunal has directed the Supreme Court-appointed monitoring committee, the CPCB and the DPCC to look into illegal dyeing units in the national Capital.

The tribunal also directed the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) to jointly file an action taken report on the compliance status in respect of the units named in the application.

The green panel was hearing a petition claiming that dyeing

factories were operating without consent or permission in the Bindapur, Matiala, Ranhola, Khyala, Meethapur, Badarpur, Mukundpur and Kirar areas of the national capital.

A bench of Chairperson Justice AK Goel said the monitoring committee appointed by the Supreme Court has to look into the matter in coordination with other authorities concerned, including the CPCB and the DPCC.

In 2004, the Supreme Court directed the shifting or closure of industrial activities operating in violation of the master plan of Delhi and also laid down the monitoring mechanism.

For stopping illegal industrial activities, the apex court formed a monitoring committee comprising Delhi's chief secretary, police commissioner, municipal commissioner and the Delhi Development Authority vice-chairman.

"The report may mention consent status and compliance status with reference to disposal of effluents into the drain location of these units in the non-conforming areas and proposed remedial actions within three months," the bench, also comprising Judicial Member Justice Sudhir Agarwal and Expert Member A Senthil Vel, said.

The matter has been posted for further proceedings on October 4.

The petition alleged that there are over 500 such factories discharging effluents in open areas, the Najafgarh drain or the Swaroop Nagar drain, besides illegally extracting groundwater. It also alleged that there are no common effluent treatment plants for treating the effluents.

"Testing of water quality in the area shows high pH, turbidity, bad odour, total dissolved solids, total suspended solids, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, chloride, nitrate, sulphuric acid, heavy metals and low dissolved oxygen. Effluents are highly toxic, carcinogenic and hazardous to the health of the people residing nearby," the petition had said.

The petition had named 21 "illegal" units.

Central Vista project, including new Parliament, faced many court cases

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The ambitious redevelopment project of the nation's power corridor, Central Vista, which includes the new Parliament building inaugurated on Sunday, faced several legal challenges in the last few years.

The project was announced in September 2019 and Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the new Parliament building on December 10, 2020.

All the controversies or disputes related to the project have been invariably landing in the Delhi High Court and the Supreme Court, the latest being a PIL by a lawyer seeking a direction to the Lok Sabha Secretariat for the inauguration of the new Parliament building by President Droupadi Murmu. Two days before the inauguration of Parliament by Prime Minister Modi, a vacation bench of the top court junked the PIL filed by Tamil Nadu-based lawyer Jaya Sukin.

The first court case against the project was filed in 2020 in the Delhi High Court by Rajeev Suri and Anuj Srivastava and others assailing the grant of Environmental Clearance and the approval by the Delhi Urban Art Commission (DUAC) and the Heritage Conservation Committee for land use change as per the DDA Act and selection of design consultant.

On February 11, 2020, a single judge bench of Justice Rajiv Shakdher of the high court directed the Delhi Development Authority (DDA) to approach the court before notifying any change to the Master Plan for going ahead with the project. The Centre challenged the order before a division bench of the high court which on February 28, 2020, stayed its single judge's direction to the DDA.

Later, the top court, in March 2020, transferred to itself the matter from the Delhi High Court in "larger public interest" and it also heard other fresh petitions challenging the project together. The Supreme Court, on January 5, 2021, came out with its verdict and, by a majority of 2:1, gave the green signal to the Rs 13,500 -crore Central Vista revamp project, holding there was "no infirmity" in the grant of environment clearance and permissions for change of land use.

Then, in April 2021, translator Anya Malhotra and historian and documentary filmmaker Sohail Hashmi filed a PIL in Delhi High Court seeking suspension of construction work, raising health and other safety concerns during the second wave of the pandemic.